various State Governments face difficulties in pushing forward this programme of Rural Employment?

SHRI S. B. CHAVAN: In 1980-81 it was a 100 per cent Centrally-sponsored scheme, which is a different basis. After the meeting of the National Development Council, 50 per cent had to be borne by the State Government, and that is why the amount is only Rs. 180 crores. In fact, almost double the amount is provided.

PROF. MADHU DANDAVATE: The States are not able to raise resources.

SHRI S. B. CHAVAN: Some States are not in a position to raise resources for financing the total Plan. But, so far as the implementation of this programme is concerned, I do not think it should present any difficulty.

श्री मोती भाई आर० चौधरी : अध्यक्ष जी में कहना चाहता हूं कि यह जो स्टेटो को धन आवंटित किया गया है वह किस आधार पर किया गया है ? क्या यह बस्तो के आधार पर किया है कि पिछड़ेपन के आधार पर किया है ? ये जो आकडें दिये गये है इनको देखने से कुछ पता नहीं चलता है कि इसको देने के लिए आपने क्या निश्चित फार्मुला अपनाया है या किस आधार पर आवंटित किया है ?

SHRI S. B. CHAVAN: It is very clear from the reply that the Gadgil formula has been modified. Now it is 60 per cent on the basis of population, 10 per cent on the basis of resource mobilisation, 10 per cent for special problems faced by the States and 20 per cent on the basis of per capita income.

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन योजना "काम के बदले अनाज" योजना का ही नया रूप है यदि यह कहा जाए कि यह नई बोतल में पुरानी शराब है तो गलत नही होंगा ।

"काम के बदले अनाज" योजना का जो अंजाम हुआ जितना रूपया उस पर लगाया गया उसका अगर 10 प्रतिशत भी काम हो जाता तो मुल्क का नक्शा ही बदला हुआ होता, लेकिन ऐसा नही हुआ । तो क्या उसी तरह से इस योजना का भी वही अंजाम होने वाला है । इस योजना का वह अंजाम न हो इसके लिए आप क्या कार्यवाही करने वाले है ।

SHRI S. B. CHAVAN: Sir, the Programme Evaluation Team was appointed by the Planning Commission and they have brought to our notice certain defects in the implementation of the scheme and we have issued instructions to all the State Governments that they should take care to see that contractors are not allowed in the implementation of this programme and other deficiencies and drawbacks which have been pointed out by the Programme Evaluation Team have also been communicated to the respective State Governments.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Increase in Minimum Wages in Mining Industry

*145. SHRI RAVINDRA VARMA: Will the Minister LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government have decided to increase the minimum wages in the mining industry; and

(b) if so, what will be the increase and from what date will the increase be effective?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR SHRIMATI RAM DULARI SINHA): (a) Preliminary notifications have been issued inviting objections/suggestions to the proposals for revision of minimum wages in respect of 27 employments in the Mining Industry included in the Schedule of the Minimum Wages Act.

(b) The proposed increase in the wage rates is 16 per cent over the

rates notified in September, 1980. The new rates of wages will come into effect from the date of issue of the final notification. Our endeavour is to issue the notication as early as possible after consulting the Minimum Wages Advisory Board.

राजस्थान में उद्योगों की स्थापना

*150. **श्री अशोक गहलोत :**
श्री बुद्धि चन्द्र जैन :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजस्थान के औद्योगिक विकास की ओर ध्यान दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या सुविधाएं दे रही है;

(ग) राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में सरकार का किस प्रकार के उद्योग स्थापित करने का विचार है;

(घ) क्या इन उद्योगों की स्थापना में राजस्थान औद्योगिक विकास निगम का कोई योगदान है; और

(ङ) यदि हां, तो कितना और यदि नहीं तो इस का क्या कारण है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी): (क) जी हां।

(ख) देश के पिछडे क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एककों में लागू की गई विभिन्न केन्द्रीय योजनाएं राजस्थान में भी उपलब्ध हैं। इनमें केन्द्रीय निवेश राजसहायता, रियायती वित्त, आयकर रियायतें, लघु एककों के लिए क्रय-खरीद सुविधाएं, परामर्शदायी सेवाएं, कच्च माल का उदारतापूर्वक आयात और जिला उद्योग केन्द्र योजना तथा केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम शामिल हैं।

(ग) और (घ). केन्द्र सरकार के अधिकारी राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के अंतर्गत पता लगाए गए चार जिलों के लिए गठित कृतिक बल (टास्क फोर्स) से संबंध है। इस कृतिक बल द्वारा इन जिलों में परियोजना की संभावनाओं और सहायक उद्योगों तथा अवस्थापना संबंधी आवश्यकताओं के क्षेत्र संबंधी रिपोर्ट दिये जाने की आशा है। केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने में राजस्थान औद्योगिक विकास निगम की भूमिका के बारे में कृतिक बल की रिपोर्ट मिल जाने के बाद ही निश्चय किया जा सकेगा।

केन्द्र सरकार को राजस्थान के अन्य पिछड़े जिलों के बारे में कोई जानकारी नहीं है तथा पिछड़े जिलों के लिए विस्तृत योजना बनाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Disruptive Forces

*151. SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that disruptive forces, who are out to destroy the secular and democratic values created during the struggle for Independence, have become very active in various parts of the country by raising the slogans of Hindu-nation, Sikh nation and Muslim nation; and

(b) if so, the steps Government have taken to politically counter these movements?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI ZAIL SINGH): (a) Some communal minded organisations and individuals have come to Government's notice for indulging in objectionable activities on the basis of religion.